

[2023] 5 एस. सी. आर 141

ओमप्रकाश सहनी

बनाम्

जय शंकर चौधरी और एक अन्य इत्यादि

(आपराधिक अपील संख्या 1331-1332/2023)

02 मई, 2023

[एम. आर. शाह और जे. बी. पारदीवाला, न्यायामूर्तिगण]

अपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – की धारा 389-तीन प्रत्यर्थियों को निचली अदालत द्वारा याचिकाकर्ता के भाई की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी-निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों द्वारा याचिका दायर कर में चुनौती दी गई थी-प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा के मूल आदेश को निलंबित करके उनकी अपीलों के अंतिम निपटारे तक जमानत पर रिहा किया जाए-उच्च न्यायालय ने सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:- न्यायालय की ओर से यह देखने का प्रयास किया जाना चाहिए कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत और निचली अदालत द्वारा स्वीकार किए गए मामले को एक ऐसा मामला कहा जा सकता है जिसमें अंततः दोषी को बरी किए जाने की उचित संभावना है-यह पता लगाने के लिए अभ्यास करते समय कि क्या दोषी के बरी होने की उचित संभावना है, जिस पर गौर किया जाना चाहिए वह स्पष्ट है-कुछ ऐसा जो अभिलेख के पटल पर बहुत स्पष्ट या ठोस है, जिसके आधार पर न्यायालय प्रथम दृष्टया इस संतुष्टि पर पहुंच सकता है कि दोषसिद्धि धारणीय नहीं हो सकती है-अपीलीय न्यायालय को धारा 389 के स्तर पर साक्ष्य की फिर से मूल्यांकन नहीं करनी चाहिए। और अभियोजन पक्ष के मामले में यहाँ या वहाँ कुछ खामियों या कमियों को उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यह सही दृष्टिकोण नहीं है-वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, प्राथमिकी में कुछ ओवर-राइटिंग आदि जैसे मुद्दों

पर गौर किया है-इन सभी पहलुओं पर दोषियों द्वारा दायर याचिकाओं की अंतिम सुनवाई के समय गौर करना होगा-उच्च न्यायालय ने दोषियों की सजा के मूल आदेश को निलंबित करने में और उनकी आपराधिक याचिकाओं के अंतिम निपटारे से पहले जमानत पर उनकी रिहाई करने में गंभीर त्रुटियां की-उच्च न्यायालय का आदेश दरकिनार कर दिया गया-दोषियों को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अवधारित किया:

1.1. विजय कुमार के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या जैसे गंभीर अपराध से जुड़े मामले में जमानत के अनुरोध पर विचार करते समय, अदालत को अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप की प्रकृति, जिस तरीके से अपराध करने का आरोप लगाया गया है, अपराध की गंभीरता और हत्या के गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की वांछनीयता जैसे प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए। [कंडिका 31] [162-जी]

2. अतः न्यायालय की ओर से यह देखने का प्रयास किया जाना चाहिए कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत और निचली अदालत द्वारा स्वीकार किए गए मामले को ऐसा मामला कहा जा सकता है जिसमें अंततः दोषी के बरी होने की अनुकूल संभावना हो। यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर एक आवश्यक परिणाम के रूप में सकारात्मक होना है, यदि अंततः दोषी इस न्यायालय के हाथों बरी होने का हकदार प्रतीत होता है, तो उसे याचिका के समापन तक काफी लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे नहीं रखा जाना चाहिए, जिसमें आमतौर पर निर्णय और निपटान में बहुत लंबा समय लगता है। हालांकि, यह पता लगाने के लिए अभ्यास करते समय कि क्या दोषी के बरी होने की उचित संभावना है, जिस पर गौर किया जाना चाहिए वह कुछ स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ ऐसा जो अभिलेख में बहुत स्पष्ट या ठोस है, जिसके आधार पर न्यायालय प्रथम दृष्टया इस संतोष पर पहुंच सकता है कि दोषसिद्धि धारणीय नहीं हो सकती है। अपीलीय न्यायालय को आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के स्तर पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए और अभियोजन पक्ष के मामले में यहां या वहां कुछ खामियों या कमियों को उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस तरह का तरीका सही नहीं होगा। [कंडिका 33] [163-बी-डी]

3. प्रस्तुत मामले में, उच्च न्यायालय ने जो किया है वह कुछ अस्वीकार्य है। उच्च न्यायालय ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, प्राथमिकी में कुछ ओवर-राइटिंग आदि जैसे मुद्दों पर गौर किया है। दोषियों द्वारा दायर अपीलों की अंतिम सुनवाई के समय इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। अभिलेख पर साक्ष्य की सरसरी जाँच करने पर, यह अदालत दोषियों के वरिष्ठ वकील से आने वाली दलीलों से सहमत होने में असमर्थ है कि या तो दोषियों के खिलाफ कोई मामला ही नहीं है या उनके खिलाफ सबूत इतने कमजोर और शक्तिहीन प्रकृति के हैं कि अंततः सभी संभावनाओं में कार्यवाही उनके पक्ष में समाप्त हो जाएगी। इसी कारण से यह अदालत दोषियों से उनके वरिष्ठ वकील के माध्यम से आ रही इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ रही कि जब तक वे आरोपों से दोषमुक्त नहीं पाए जाते, तब तक उन्हें काफी लंबे समय तक सलाखों के पीछे रखना अर्थहीन, अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। [कंडिका 34] [163-ई-जी]

4. मामले के समग्र दृष्टिकोण से, यह न्यायालय आश्चर्य है कि उच्च न्यायालय ने दोषियों की सजा के मूल आदेश को निलंबित करने और उनकी आपराधिक अपीलों के अंतिम निपटारे तक जमानत पर उनकी रिहाई में गंभीर त्रुटियाँ की हैं। [कंडिका 35] [163-एच]

राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पु यादव बनाम सी. बी. आई. (2007) 1 एससीसी 70:[2006] 9 पूरक।एससीआर 40; एश मोहम्मद बनाम. शिव राज सिंह उर्फ लल्ला बाबू और एक अन्य (2012) 9 एससीसी 446:[2012] 7 एससीआर 584; भगवान राम शिंदे गोसाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य (1999) 4 एस. सी. सी. 421:[1999] 3 एससीआर 545; सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2008) 5 एस. सी. सी. 230:[2008] 8 एससीआर 220; अतुल त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2014) 9 एससीसी 177:[2014] 14 एससीआर 1188-पर निर्भर

किशोरी लाल बनाम रूपा और अन्य (2004) 7 एस. सी. सी. 638: [2004] 4 पूरक।एससीआर 628; विजय कुमार बनाम नरेंद्र और अन्य (2002) 9 एस. सी. सी. 364; रामजी प्रसाद बनाम रतन कुमार

जायसवाल और एक अन्य (2002) 9 एस. सी. सी. 366; वसंत तुकाराम पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 5 एस. सी. सी. 281: [2005] 3 एस. सी. आर. 630; गोमती बनाम ठाकुरदास और अन्य (2007) 11 एससीसी 160:[2007] 5 एस. सी. आर. 90-को संदर्भित।

कानूनी मामले का संदर्भ

[2006] 9 पूरक. एस. सी. आर. 40	पर निर्भर	पैरा 25
[2012] 7 एससीआर 584	पर निर्भर	पैरा 26
[1999] 3 एस. सी. आर. 545	पर निर्भर	पैरा 27
[2008] 8 एससीआर 220	पर निर्भर	पैरा 28
[2014] 14 एससीआर 1188	पर निर्भर	पैरा 29
[2004] 4 पूरक।एस. सी. आर. 628	को संदर्भित	पैरा 30
[2005] 3 एस. सी. आर. 630	को संदर्भित	पैरा 32
[2007] 5 एस. सी. आर. 90	को संदर्भित	पैरा 32

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक याचिका संख्या 1331-1332/2023

2021 के सी. आर. ए. डी. बी. सं. 322 और 411 में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 16.09.2022 से

आर. चंद्रचूड़, सुश्री फौजिया शकील, अगस्त्य सेन, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता।

वी. के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, राकेश कुमार, शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, चांद कुरैशी, सी. थंगराजा, एस. कृष्णमूर्ति, के. कुमारवादिवेल, मनीष कुमार, प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति

1. ये अपीलें मूल प्रथम सूचनादाता (मृतक के भाई) के निर्देश पर हैं और पटना उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः 2021 की आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 322 और 2021 की आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 411 में पारित एक संयुक्त आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने यहाँ पर प्रतिवादी संख्या 1,3 और 4 (दोषी) पर निचली अदालत द्वारा लगाए गए आजीवन कारावास की सजा के मूल आदेश को निलंबित कर दिया और ऊपर उल्लिखित दो आपराधिक याचिकाओं के अंतिम निपटारे तक उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

तथ्यात्मक पहलू

2. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर प्रतिवादी सं क्रमशः 1,3 और 4 पर छह अन्य सह-अभियुक्तों के साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VII, वैशाली, हाजीपुर, जिले हाजीपुर में वैशाली (बिहार) के न्यायालय में सत्र विचारन संख्या 280/2019 में मुकदमा चलाया गया था: जो कि धारा 302, 120-B, 506 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है क्रमशः सपठितभारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 (संक्षेप में, 'आई. पी. सी.') और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 (संक्षेप में, '1959 अधिनियम')

3. इनमें क्रमशः जय शंकर चौधरी, अभय कुमार और राम बाबू नामक तीन प्रत्यर्थियों को निचली अदालत द्वारा याचिकाकर्ता के भाई मनीष कुमार की हत्या के अपराध का दोषी ठहराया गया था। अन्य सह-अभियुक्तों को बरी करने का आदेश दिया गया।

4. प्रतिवादी संख्या क्रमशः 1,3 और 4 ने निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।

5. निचली अदालत द्वारा अपने दिनांक 12.03.2021 के फैसले में वर्णित अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है:

"प्रस्तुत मामले में सूचना देने वाले ओम प्रकाश सहनी के लिखित आवेदन के आधार पर 14.08.2018 को एफ. आई. आर.(प्रथम सूचना प्रतिवेदन) दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सूचना देने वाले ओम प्रकाश सहनी 13-08-2018 को लगभग अपराहन 10:00 बजे अपने छोटे भाई मनीष कुमार, प्रखंड प्रमुख, जंदाहा के साथ अपनी आल्टो कार से प्रखंड जंदाहा स्थित प्रखंड प्रमुख के कार्यालय पहुंचे। सूचक का भाई अपने कक्ष में गया।बी. डी. ओ. (प्रखंड विकास पदाधिकारी) का चालक अपनी कार में आया और प्रमुख को बताया कि बी. डी. ओ. (प्रखंड विकास पदाधिकारी)ने उन्हें बुलाया फोन किया है और ऐसी सूचना पर प्रखंड प्रमुख मनीष कुमार बी. डी. ओ. की कार में बी. डी. ओ. के आवास पर गए।कुछ समय बाद प्रमुख उसी वाहन से वापस आए और जब वे लगभग अपराहन 03:00 बजे अपने कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। आरोपी जय शंकर चौधरी और अभय कुमार आए और आरोपी राम बाबू सहनी द्वारा उसे मारने के लिए उकसाने पर सूचक के भाई, प्रखंड प्रमुख पर गोलियां चला दीं। सूचक का भाई जमीन पर गिर गया और दोनों आरोपी अपनी पिस्तौल लहराते हुए महुआ रोड की ओर मोटरसाइकिल पर भाग गए। अन्य दो आरोपी राम बाबू सहनी और बिनोद चौधरी भी उसी दिशा में एक-दूसरे मोटरसाइकिल पर घटना स्थल से भाग गए।एफ. आई. आर. ने आगे कहा गया है कि सूचना देने वाला और प्रमुख का चालक अनिल कुमार घटना के समय कुछ अन्य लोगों के साथ मौजूद थे। वे उसे डॉक्टर बिंदु झा के क्लीनिक पर ले गए और उसके निर्देश पर वे घायल को हाजीपुर के गणपति अस्पताल ले गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद वे मृतक को हाजीपुर सदर अस्पताल ले गए, जहां अन्त्य परीक्षण किया गया और पुलिस भी वहां पहुंची और आगे की कार्रवाई की।प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि प्रखंड प्रमुख का चुनाव 02-08-2018 को आयोजित किया गया था और प्रमुख ने चुनाव जीता था। पुत्र सूचना देने वाले ने एफ. आई. आर. यह भी बताया है कि उमेश सिंह कुशवाहा, एम. एल. ए., महनार, बिनोद चौधरी पुत्र राम लखन चौधरी, अजीत कुमार पुत्र राम बाबू सहनी ग्राम दुलौर थाना जंदाहा, कुंदन सहनी (प्रखण्ड शिक्षक) पुत्र राम नंदन सहनी ग्राम नरहरपुर, रणधीर कुमार पुत्र स्वर्गीय मसुदन प्रसाद सिंह गाम नरहरपुर, रंजीत कुमार पुत्र राम वृक्ष सिंह ग्राम नरहरपुर, सभी थाना जंदाहा और अजय ठाकुर (शिक्षक) संकुल साधन सेवी, जंदाहा ग्राम नारी खुर्द थाना पातेपुर

जिला वैशाली ने सूचक को पहलेम विंदी चौक सड़क (सुरेश चौक से उत्तर) पर धमकी दी थी कि वे सूचक के भाईको चुनाव नहीं जीतने देंगे, और अगर वह जीत जाता है तो, वे उसको जीने नहीं देंगे।सूचक का यह भी कहना है कि इन लोगों ने उसे कई बार धमकी दी और उसने अपने भाई को इस बात की जानकारी दी।वर्तमान प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जंदाहा ने यह भी धमकी दी कि उन्हें प्रमुख को प्रखण्ड शिक्षक की भर्ती में नहीं उलझने के लिए सूचिक कर देना चाहिए अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।सूचक का मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने साजिश के तहत यूखक के भाई मनीष कुमार की हत्या को अंजाम दिया है।

6. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों से निम्नानुसार पूछताछ की:

पी. डब्ल्यू. 1 राज कुमार सहनी,

पी. डब्ल्यू. 2 अनिल कुमार सहनी,

पी. डब्ल्यू. 3 रूप कला देवी,

पीडब्लू 4 डॉ. शशिधर कुमार,

पीडब्लू 5 लाल बाबू सहनी,

पी. डब्ल्यू. 6 लालदेव सहनी,

पी. डब्ल्यू. 7 ओम प्रकाश सहनी/सूचक,

पी. डब्ल्यू. 8 सरोज कुमार सिंह,

पी. डब्ल्यू. 9 शोभकांत पासवान (जांच अधिकारी) और

पी. डब्ल्यू. 10 सुनील कुमार सिंह (जांच अधिकारी)।

7. निचली अदालत ने अभिलेख पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद, अंतिम विश्लेषण में क्रमशः पैरा 40 और 41 में निम्नानुसार देखा:

"40. पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा की गई प्रस्तुतियों और बचाव पक्ष के विद्वान वकीलों द्वारा की गई जिरह सहित अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के संयुक्त अवलोकन पर

विचार करने के बाद इस अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि 13-08-2018 को, लगभग अपराहन 03:00 बजे जंदाहा प्रखंडपर आरोपी राम बाबू सहनी और बिनोद चौधरी ने जय शंकर चौधरी और अभय कुमार सहनी को मनीष सहनी को मारने के लिए उकसाया। इस तरह के उकसावे पर जय शंकर चौधरी और अभय कुमार सहनी ने मनीष सहनी पर गोली चला दी। इसके बाद उन्हें जंदाहा में चिकित्सक बिंदु झा के पास ले जाया गया और वहां से उन्हें हाजीपुर रेफर कर दिया गया। उन्हें एम्बुलेंस से हाजीपुर गणपति अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीडब्लू-7/सूचक के साक्ष्य के अनुसार, मनीष सहनी उनके और चालक पीडब्लू 2 के साथ लगभग अपराहन 1:00 बजे जंदाहा प्रखंड पहुंचे, वे उसके कक्ष में बैठे थे, जब प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपने चालक के माध्यम से उसे बुलाया और वह प्रखंड विकास पदाधिकारी के वाहन से उनके निवासी पर उनसे मिलने गया। जब वे लगभग उपराह्न 03:00 बजे लौटे, जब वह अपने कक्ष की ओर जा रहा था, तो आरोपी राम बाबू सहनी और बिनोद चौधरी ने जय शंकर चौधरी और अभय कुमार सहनी को मनीष सहनी को मारने के लिए उकसाया। इस तरह के उकसावे पर जय शंकर चौधरी और अभय कुमार सहनी ने मनीष सहनी पर गोली चला दी और वह जमीन पर गिर गया। चारों आरोपी उत्तरी गेट से महुआ रोड की ओर भाग गए। इसके बाद मनीष सहनी को जंदाहा में चिकित्सक बिंदु झा के पास ले जाया गया और वहां से उन्हें हाजीपुर रेफर कर दिया गया। उन्हें एम्बुलेंस से हाजीपुर गणपति अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हाजीपुर के सदर अस्पताल में उनका शव परीक्षण किया गया। प्रश्रुत घटना के पीछे का कारण यह है कि आरोपी जय शंकर चौधरी पहले प्रखंड प्रमुख चुने गए थे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में मनीष सहनी से हार गए थे। मनीष सहनी तब प्रखंड प्रमुख बन गए। सभी अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में कहा गया है कि वे कथित अपराध करने की साजिश में शामिल थे। पीडब्लू 1 राज कुमार सहनी ने अपने साक्ष्य में साबित किया है कि प्रमुख मनीष सहनी प्रखंड विकास पदाधिकारी के वाहन से आए थे और अपने कक्ष की ओर जा रहे थे, जब आरोपी जय शंकर ने एक अन्य के साथ मनीष सहनी पर गोलियां चला दीं। उसने कहा है कि यह जय शंकर था, जिसने मनीष सहनी को गोली मारी थी। पी. डब्ल्यू. 2, ब्लॉक प्रमुख के चालक अनिल कुमार सहनी

ने भी साबित किया कि मनीष सहनी प्रखंड विकास पदाधिकारी के वाहन से आए थे। आरोपी जय शंकर चौधरी और अभय कुमार सहनी पहले से ही वहां मौजूद थे। दूसरे आरोपी राम बाबू सहनी और बिनोद चौधरी वहाँ पहुँचे और कहा "क्या देखते हो गोली मारो"। जय शंकर चौधरी ने गोली चलाई और उसके बाद अभय कुमार ने दूसरी गोली चलाई। प्रमुख जमीन पर गिर गया और सुचक और गवाह पी. डब्ल्यू. 2 के बारे में कहा जाता है कि वे उसे जंदाहा के अस्पताल ले गए, जहाँ से उसे हाजीपुर सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पी. डब्ल्यू. 3 मृतक की पत्नी चश्मदीद गवाह नहीं है। हालाँकि, उसने गवाहों द्वारा बताए गए तरीके से आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपने पति की मृत्यु की गवाही दी है। इन तथ्यों के अलावा, उन्होंने यह भी कहा है कि जब उनके पति ने चुनाव जीता तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी और उन्होंने अपने पति को सतर्क रहने की सलाह दी थी। पी. डब्ल्यू. 5 ने अपने मुख्य वक्तव्य में घटना की तारीख और समय यानी 13-08-2018 को अपराहुन 03:00 बजे पर साबित किया है: वह, एक चश्मदीद गवाह, अभियोजन पक्ष की कहानी की भी गवाही देता है कि आरोपी जय शंकर चौधरी और अभय कुमार ने राम बाबू सहनी और बिनोद चौधरी के उकसावे और प्रोत्साहन पर मनीष सहनी पर गोली चला दी थी। पी. डब्ल्यू. 6 ने भी अपने मुख्य बयान में कथित घटना की तारीख 13-08-2018 और समय अपराहुन 03:00 बजे को साबित किया है। वह घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है और गवाही देता है कि बिनोद चौधरी और राम बाबू बाइक से आए और जय शंकर चौधरी और एक अन्य व्यक्ति को प्रोत्साहित किया, जिसे उसने नहीं पहचाना। इस तरह के उकसावे और प्रोत्साहन पर, जय शंकर चौधरी और दूसरे ने मनीष सहनी पर गोलियां चला दीं। पीडब्लू 8 सरोज कुमार सिंह भी एक चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हैं और इस तथ्य की गवाही देते हैं कि बिनोद चौधरी के उकसावे पर आरोपी जय शंकर चौधरी ने मनीष सहनी पर गोली चला दी और वह दूसरे व्यक्ति की पहचान नहीं करता है, जिसने भी मनीष सहनी पर भी गोली चलाई थी। हालाँकि, घटना की तारीख का पीडब्लू-8 द्वारा 30.08.2018 होने का खंडन किया गया है। अभियुक्त बिनोद चौधरी जिसका नाम बार-बार साक्ष्य में प्रकट हो रहा है। अदालत के समक्ष तत्काल मुकदमे का सामना नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को साबित कर दिया है और उस पर जो

जख्म वो दो प्रवेश घाव हैं, एक-एक बाई ऊपरी छाती पर और एक एपिगास्ट्रियम पर, दो निकास घावों के साथ, एक दाएं सब कोस्टल क्षेत्र में पश्च अक्षीय रेखा पर और दूसरा दाएं कटि (कमर) क्षेत्र में पश्च अक्षीय रेखा में। जाँच करने वाले दो जाँच अधिकारी जाँच प्रक्रिया की वास्तविकता को उसी तरह से साबित कर चुके हैं जैसा कि पिछले पैराग्राफों (अनुच्छेदों) में चर्चा की गई है। बचाव पक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए और साबित किए गए तथ्यों को गलत साबित करने के लिए ऐसी सामग्री या विरोधाभास या कोई अन्य सबूत रिकॉर्ड (अभिलेख) पर नहीं ला सका।

41. इसलिए, सामग्री और मौखिक और दस्तावेजी दोनों सबूतों के आधार पर, जैसा कि अभिलेख में उपलब्ध है, यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी जय शंकर चौधरी, अभय कुमार उर्फ अभय सहनी और राम बाबू सहनी के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है कि राम बाबू सहनी के उकसाने पर, अन्य दो आरोपी जय शंकर चौधरी और अभय कुमार उर्फ अभय सहनी ने मनीष सहनी पर गोलियां चला दीं, जिससे उसकी मौत हो गई और इस तरह उसकी हत्या कर दी गई। यह अदालत उन्हें अपने संयुक्त इरादे को आगे बढ़ाते हुए मनीष साहनी की हत्या करने का दोषी पाती है।

8. हमारे समक्ष उपस्थित तीनो दोषी अर्थात प्रतिवादी संख्या क्रमशः 1, 3 और 4 ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा के मूल आदेश को निलंबित करके उनकी याचिकाओं के अंतिम निपटारे तक जमानत पर रिहा किया जाए।

9. उच्च न्यायालय ने तीनों दोषियों की सजा के मूल आदेश को निलंबित कर दिया और दिनांक 16.09.2022 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VII, हाजीपुर द्वारा जनदाहा थाना मामला संख्या 202/2018 से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या 280/2019 में पारित दिनांक 12.03.2021 के आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और दिनांक 15.03.2021 के सजा के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार सजा सुनाई गई है:

याचिकाकर्ता का नाम	धारा के अंतर्गत दोषी	सजा		
		कारावास	जुर्माना (रु.)	जुर्माना न अदा करने पर
आराधिक याचिका (डी बी) संख्या322/2021				
जय शंकर चौधरी	302/34 भा. दं. सं.	आजीवन कठोर कारावास	50,000/-	छः महीने के लिए कठोर कारावास
	शस्त्र अधिनियम की 27	पाँच वर्षों का कठोर कारावास	--	--
आराधिक याचिका (डी बी) संख्या 411/2021				
अभय कुमार	302/34 भा. दं. सं.	आजीवन कठोर कारावास	50,000/-	छः महीने के लिए कठोर कारावास
	शस्त्र अधिनियम की 27	पाँच वर्षों का कठोर कारावास	--	--
राम बाबू सहनी	302/34 भा. दं. सं.	आजीवन कठोर कारावास	50,000/-	छः महीने के लिए कठोर कारावास

जुमाने की राशि का 75 प्रतिशत मृतक मनीष सहनी की विधवा रूप कला देवी को देने का आदेश दिया गया है और 25 प्रतिशत राशि बिहार राज्य को देने का आदेश दिया गया है।

इस न्यायालय के दिनांक 03.08.2022 के आदेश के अनुपालन में, राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 (1) के पहले प्रावधान के अनुसार एक लिखित आपत्ति दायर की है।

हमने आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 322/2021 में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री वसंत विकास को श्री संजय सिंह, आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 411/2021 में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील और राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक को सुना है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि एक सार्वजनिक स्थान पर 13.08.2018 को अपराहुन 03:00 बजे हुई कथित घटना के बारे में, सूचना देने वाले (पी.डब्ल्यू.-7) की अपराहुन 10:00 बजे जमा की हुई लिखित रिपोर्ट के आधार पर 14.08.2018 को प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई। सूचना देने वाले ने घटना के चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है। हालांकि, लिखित प्रतिवेदन देर से जमा करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जिसमें इन याचिकाकर्ताओं को हमलावरों के रूप में नामित किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि मृतक और इन याचिकाकर्ताओं के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इन याचिकाकर्ताओं द्वारा मृतक की हत्या के कारण के रूप में प्रकट किया गया है। तदनुसार वे प्रस्तुत करते हैं कि मुख्य हमलावरों के रूप में प्रथम सूचना प्रतिवेदन में इन याचिकाकर्ताओं के नामों का खुलासा बाद में विचारपूर्वक किया गया है और उस पृष्ठभूमि में, प्रथम सूचना प्रतिवेदन का देर से पंजीकरण अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि हालांकि (पी.डब्ल्यू.-7), सूचक ने घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है, जिसने मृतक को घायल अवस्था में पास के अस्पताल और उसके बाद सदर अस्पताल लेकर गया था, जब मृतक को एक निजी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था; उसका अपना बयान इस संस्करण का खंडन करता है जैसा

कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में कहा गया है क्योंकि जिरह के दौरान एक सवाल के जवाब में, उसने स्वीकार किया कि वह मृतक के साथ सदर अस्पताल नहीं गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि हालाँकि याचिकाकर्ताओं को मुकदमे के दौरान जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया गया था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने मुकदमे के दौरान इन याचिकाकर्ताओं की पहचान की थी।

जमानत के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना का विरोध करते हुए विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि याचिकाकर्ता मुख्य हमलावर हैं, जैसा कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में खुलासा किया गया है, जिसकी पुष्टि मुकदमे के दौरान सभी चश्मदीद गवाहों द्वारा की गई है, जो अपने बयानों पर संगत रहे हैं और यह एक स्वीकृत तथ्य है कि मृतक और इन याचिकाकर्ताओं के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्वीता थी इस तरह की दुश्मनी चश्मदीद गवाहों के बयान में विश्वास जोड़ती है।

हमने निचली अदालत के आक्षेपित फैसले और आदेश का अध्ययन किया है। हमने पक्षों की ओर से प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अपना चिंतित विचार दिया है। हमने निचली अदालत के अभिलेख के साथ उपलब्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन की मूल प्रति को पढ़ा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सूचना देने वाले (पी.डब्ल्यू.-7) की उक्त लिखित रिपोर्ट थाना में जमा करने की तारीख के संबंध में ओवर-राइटिंग हुई है।

यह अभियोजन पक्ष का मामला है, जैसा कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में खुलासा किया गया है और साथ ही मुकदमे में भी स्थापित किया गया है, कि प्रखंड कार्यालय में 13.08.2018 को अपराहुन 03:00 बजे यह घटना हुई थी। मृतक उक्त प्रखंड का प्रमुख था।

प्रथम सूचना प्रतिवेदन में यह दावा किया गया है कि जब सूचक और मृतक प्रखंड कार्यालय में अपने (मृतक के) कक्ष में प्रवेश करने वाले थे, तो याचिकाकर्ता जय शंकर चौधरी और अभय कुमार ने आरोपी राम बाबू साहनी के उकसावे पर गोलियां चला दीं। कहा जाता है कि सूचक और अन्य लोग घायल हालत में मृतक को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद मृतक के शव को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार की गई

और उसी तारीख 13.08.2018 को पोस्टमार्टम भी किया गया। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई प्रस्तुति में तत्व पाते हैं कि सूचना देने वाले के लिए अगले दिन 1 बजे अपना लिखित बयान दायर करने के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं था। जिसमें इन याचिकाकर्ताओं को मुख्य हमलावरों के रूप में पेश किया गया है। इसके अलावा, सूचना देने वाला (पी.डब्ल्यू.-7) प्रथम दृष्टया सच्चा प्रतीत नहीं होता है, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को देखते हुए कि मृतक के शव को ग्रामीणों द्वारा अस्पताल ले जाया गया था, न कि सूचना देने वाले द्वारा।

मामले के उपर्युक्त विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारे विचार में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 389 (1) के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करने के उद्देश्य से, प्रथम सूचना प्रतिवेदन के पंजीकरण के लिए लिखित रिपोर्ट दाखिल करने में असामान्य देरी अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने के लिए एक वैध आधार प्रतीत होता है।

ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं की ओर से जमानत पर उनकी रिहाई के लिए की गई प्रार्थना की अनुमति है।

याचिकाकर्ता जय शंकर चौधरी [2021 की आपराधिक याचिका (डी. बी.) संख्या 322 में], अभय कुमार उर्फ अभय साहनी और राम बाबू साहनी [2021 की आपराधिक याचिका (डी. बी.) संख्या 411 में] को याचिका की प्रलंबता के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उन्हें 10,000/- (दस हजार) रु का जमानतनामा देना होगा, और साथ ही समान राशि की दो प्रतिभूतियाँ देनी होंगी जो जादह थाना मामला सं.202/2018 से उद्भूत 2019 की सत्र सुनवाई सं. 280 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VII, वैशाली हाजीपुर को सुतुष्ट कर सकें।

इस बीच सजा निलंबित रहेगी। जुर्माने की वसूली पर भी रोक रहेगी।”

(जोर दिया गया)

10. मूल प्रथम सूचक (मृतक का भाई) उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण हमारे समक्ष अपील में आया है।

याचिकाकर्ता की ओर से

11. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री आर. चंद्रचूड़ ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में एक गंभीर त्रुटि की है, जिसमें आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'दंड प्रक्रिया संहिता') की धारा 389 के तहत उच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, उनकी सजा के मूल आदेश को निलंबित करके उनकी संबंधित अपीलों के अंतिम निपटारे तक तीनों दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

12. विद्वान वकील ने कहा है कि एक बार जब आरोपी हत्या जैसे बहुत गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया जाता है, तो निर्दोष होने का अनुमान अब मौजूद नहीं रहेगा और उच्च न्यायालय से उम्मीद है कि जमानत देने में बहुत सावधानी बरतें। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने सजा के मूल आदेश के निलंबन के लिए तीन दोषियों की याचिका पर विचार करते हुए साक्ष्य की वस्तुतः सराहना की है। उच्च न्यायालय आजीवन कारावास की सजा के निलंबन के लिए दोषियों की याचिका पर विचार करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट में अति-लेखन, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अत्यधिक देरी आदि जैसे मुद्दों पर विचार नहीं करना चाहिए था।

13. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला नेत्र साक्ष्य पर आधारित है। निचली अदालत के याचिकाकर्ता, जो घटना के चश्मदीद गवाहों में से एक है, के बयान पर विश्वास करने और उसे स्वीकार करने के बाद, उच्च न्यायालय आजीवन कारावास की सजा के मूल आदेश को इतने हल्के और आकस्मिक रूप से निलंबित नहीं कर सकता था।

14. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि उसकी अपीलों में योग्यता होने के कारण, उन्हें अनुमति दी जा सकती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य आदेश को रद्द किया जा सकता है।

प्रतिवादी संख्या क्रमशः 1, 3 और 4 (दोषी) की ओर से प्रस्तुतियाँ

15. दूसरी ओर दोषियों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. के. शुक्ला ने अपीलों का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालत द्वारा संबंधित दोषियों पर लगाए गए सजा के मूल आदेश को निलंबित करने वाले आक्षेपित आदेश को पारित करने में उच्च न्यायालय द्वारा कानून की कोई भी त्रुटि नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया पूरा मामला अत्यधिक संदिग्ध और राजनीति से प्रेरित है। अभियोजन पक्ष ने घटना के वास्तविक स्रोत को दबा दिया है। वह प्रस्तुत करते हैं कि उसके मुवक्किलों को कथित अपराध में गलत तरीके से फंसाया गया है।

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 389 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक विवेकाधीन आदेश पर गौर करते हुए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को पूरी तरह से अस्पष्ट या विकृत नहीं कहा जा सकता है और ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय आक्षेपित आदेश को बाधित नहीं कर सकता है।

17. अंत में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलों को अंतिम सुनवाई के लिए आने में वर्षों लगेंगे और उस अवधि के लिए उनके मुवक्किल जेल में पड़े रहेंगे। वह प्रस्तुत करते हैं कि उसके मुवक्किलों के आपराधिक याचिकाओं में बरी होने की बहुत उचित संभावना है और ऐसी परिस्थितियों में, अगर उन्हें उनकी संबंधित आपराधिक अपीलों के अंतिम निपटारे तक जमानत पर रहने की अनुमति दी जाती है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

18. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रार्थना की कि अपीलों में कोई योग्यता नहीं होने के कारण, उन्हें खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषण

19. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई त्रुटियाँ की हैं?

दं. प्र. सं. की धारा 389 और सजा की निलंबन पर कानून:

20. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 इस पढ़ा जाता है

"389. अपील लंबित रहने तक सजा का निलंबन; याचिकाकर्ता की जमानत की रिहाई-(1) किसी दोषी व्यक्ति द्वारा की गई याचिका के लंबित रहने तक अपीलीय न्यायालय, उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों के लिए, आदेश दे सकता है कि जिस सजा या आदेश के खिलाफ याचिका हैं के निष्पादन को निलंबित किया जाए और, यदि वह कारावास में है, तो उसे जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जाए। बशर्ते कि अपीलीय न्यायालय, जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा करने से पहले, एक दोषी व्यक्ति जो मौत या आजीवन कारावास या कम से कम दस साल की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के खिलाफ लिखित में कारण दिखाने का अवसर देगा:

बशर्ते कि उन मामलों में जहां एक दोषी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाता है, लोक अभियोजक के लिए जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति होगी।

(2) इस धारा द्वारा किसी अपीलीय न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा उसके अधीनस्थ न्यायालय में दोषी व्यक्ति द्वारा की गई याचिका के मामले में भी किया जा सकता है।

(3) जहां दोषी व्यक्ति उस न्यायालय को संतुष्ट करता है जिसके द्वारा वह दोषी ठहराया गया है कि वह एक अपील प्रस्तुत करने का इरादा रखता है, तो न्यायालय -

(i) जहां ऐसे व्यक्ति जो जमानत पर है जिसको तीन साल से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है, या

(ii) जहां वह अपराध जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषी ठहराया गया है, वह जमानती है और वह जमानत पर है,

आदेश दें कि दोषी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाए, जब तक कि जमानत से इनकार करने के लिए विशेष कारण न हों, ऐसी अवधि के लिए जो अपील प्रस्तुत करने और उप-धारा (1) के तहत अपीलीय न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दे, और कारावास की सजा, जब तक वह जमानत पर रिहा होता है, तब तक निलंबित माना जाएगा।

(4) जब याचिकाकर्ता को अंततः किसी अवधि के लिए कारावास या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो जिस अवधि के दौरान उसे इस प्रकार रिहा किया जाता है, उसे उस अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसे इस प्रकार सजा सुनाई गई है।

21. निलंबन स्थगन या अस्थायी रूप से किसी स्थिति को जारी रखने से रोकता है। ब्लैक के कानूनी शब्दकोश (सातवां संस्करण) के अनुसार, 'सस्पेंड' शब्द का अर्थ है, अन्य बातों के साथ-साथ, बाधित करना; स्थगित करना; टालना। ब्लैक के कानूनी शब्दकोश (सातवां संस्करण) 'निलंबन' शब्द का वर्णन करता है, जिसका अर्थ है, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी चीज़ को अस्थायी रूप से विलंबित करने, बाधित करने या समाप्त करने का कार्य। जैसा कि ऊपर बताया गया है, 'निलंबन' शब्द का वही अर्थ देते हुए, न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश (1998 संस्करण) निलंबन को अस्थायी रूप से जारी रखने या लागू करने या प्रभाव दिए जाने से रोकना या किसी कार्रवाई, घटना या निर्णय को स्थगित या विलंबित करने के रूप में वर्णित करता है।

22. इस प्रकार, जब हम दोषसिद्धि के बाद सजा के निलंबन की बात करते हैं, तो विचार सजा के निष्पादन को स्थगित करने या टालने का होता है। सजा को स्थगित करने का उद्देश्य दोषी को जेल में बंद करके हासिल नहीं किया जा सकता है; इसलिए, निष्पादन को स्थगित करने के स्वाभाविक परिणाम के रूप में, दोषी को अगले आदेश तक जमानत पर बढ़ाया जा सकता है।

23. हमारे देश में आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि एक आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता है। एक बार जब आरोपी को दोषी ठहराया जाता है,

तो निर्दोष होने की धारणा मिट जाती है। इसी तरह, यदि अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है, तो निर्दोष होने की धारणा और मजबूत हो जाती है।

24. द.प्र.सं. की धारा 389 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उप-धारा 3 की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मामले को छोड़कर न तो कानून का कोई विशिष्ट सिद्धांत निर्धारित किया गया है और न ही दोषी की प्रार्थना पर विचार करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है और इसके अलावा, सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा इसके विपरीत दर्ज किए जाने तक निर्दोषता के बारे में आरोपी के पक्ष में धारणा को मिटाते हुए दोषसिद्धि का निर्णय लेना और उपरोक्त पृष्ठभूमि में, -दोषसिद्धि से पूर्व साथ-साथ दोषसिद्धि के बाद के चरण में जमानत के लिए प्रार्थना के बीच एक अच्छा अंतर होता है, नामतः सी. आर. पी. सी. की धारा 437, 438, 439 और 389 (1)।

25. राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पु यादव बनाम सी. बी. आई. में, रिपोर्ट किया गया (2007) 1 एस. सी. सी. 70 में, यह क्रमशः पैरा 8, 9 और 10 के तहत निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

"8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तब कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1977) 4 एस. सी. सी. 291 1977 एस. सी. सी. (आपराधिक)559)] में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। उक्त निर्णय के कंडिका 2 में निम्नानुसार अवलोकन किया गया: (एस. सी. सी. पीपी. 292 -93)

"किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए पांच या छह साल की अवधि के लिए जेल में रखना वास्तव में न्याय का उपहास होगा जो अंततः उसके द्वारा नहीं किया हुआ पाया जाता है। क्या अदालत कभी उसे उसकी कैद की भरपाई कर सकती है जो अन्यायपूर्ण पाई जाती है? क्या किसी व्यक्ति को यह बताना न्यायालय के लिए उचित होगा: "हमने आपकी अपील स्वीकार कर ली है क्योंकि हमें लगता है कि आपके पास एक प्रथम दृष्टया मामला है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास आपकी अपील सुनने के लिए कुछ वर्षों तक समय नहीं है और इसलिए, जब तक हम आपकी अपील नहीं सुनते, आपको जेल में रहना चाहिए, भले ही आप निर्दोष हों? न्याय के इस तरह के प्रशासन से जनता के मन में क्या विश्वास पैदा होगा? यह काफी हद तक संभव हो सकता है, और

वास्तव में इस न्यायालय में कुछ मामलों में ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति अपनी अपील पर सुनवाई से पहले अपनी पूरी कारावास की अवधि पूरी कर लेता है। क्या एक न्यायाधीश अपील की सुनवाई के बाद ऐसे व्यक्ति को बरी करते समय पश्चाताप की भावना से अभिभूत नहीं होगा? क्या यह उनके न्याय की भावना का अपमान नहीं होगा? ऐसे व्यक्ति के लिए बरी होने का क्या लाभ होगा जो पहले ही अपनी कारावास की अवधि या किसी भी तरह से इसका एक बड़ा हिस्सा पूरा कर चुका है? इसलिए, यह नितांत आवश्यक है कि जिस प्रथा का यह न्यायालय अतीत से पालन कर रहा है, उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और जब तक यह न्यायालय किसी अभियुक्त की अपील को उचित अवधि के भीतर सुनने की स्थिति में नहीं है, तब तक न्यायालय को सामान्य रूप से, जब तक कि अन्यथा कार्य करने के लिए ठोस आधार न हों, उन मामलों में अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर देना चाहिए जहां अभियुक्त को उसकी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दी गई है।”

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तब भागीरथसिंह बनाम गुजरात राज्य [(1984) 1 एस. सी. सी. 284 1984 एस. सी. सी. (आ.) 63], शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन बनाम भारत संघ [(1996) 2 एस. सी. सी. 616:1996 एस. सी. सी. (आ.) 366], जोगिंदर कुमार बनाम यू. पी. राज्य [(1994) 4 एस. सी. सी. 260:1994 एस. सी. सी. (आ.) 1172], आदि में दिए गए इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

10. हमारी राय में कहा जा सकता है कि उपरोक्त निर्णयों में से किसी ने भी इस बारे में कोई पूर्ण और बिना शर्त नियम निर्धारित नहीं किया है कि अदालत द्वारा जमानत कब दी जानी चाहिए और कब नहीं दी जानी चाहिए। यह सब प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई पूर्ण नियम है कि क्योंकि कारावास की लंबी अवधि समाप्त हो गई है, इसलिए जमानत अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।

(जोर दिया गया)

26. यह न्यायालय, एश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह उर्फ लल्ला बाबू और अन्य के मामले में (2012) 9 एस. सी. सी. 446 में प्रतिवेदित किया और पैरा 30 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:

"30. हम उपयोगी रूप से कह सकते हैं कि जब नागरिक शांतिपूर्ण जीवन जीने से डरते हैं और इस तरह के अपराध व्यवस्थित समाज की स्थापना में बाधा डालते हैं, तो अदालत का कर्तव्य अधिक स्पष्ट हो जाता है और दायित्व बढ़ जाता है। आपराधिक पृष्ठभूमि का उचित विश्लेषण किया जाना चाहिए था। कहने की जरूरत नहीं है कि शर्तों का आरोपन एक आरोपी की जमानत स्वीकार करने के आदेश के बाद आता है। यह सवाल उठाया जाना चाहिए कि क्या आरोपी जमानत पर रिहा होने का हकदार है या नहीं और उसके बाद ही शर्तों को लागू करने का मुद्दा उठेगा। हम एक पल के लिए भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि हिरासत की अवधि एक प्रासंगिक कारक है, लेकिन साथ ही परिस्थितियों और आपराधिक पृष्ठभूमि की समग्रता पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्हें सामूहिक न्याय के पैमाने पर तौला जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संयोजन में सामाजिक चिंता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उक्त मापदंड के संबंध में हम यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि मामले में सामाजिक चिंता को अभियुक्त की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हटाने पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(जोर दिया गया)

27. भगवान राम शिंदे गोसाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य, (1999) 4 एस. सी. सी. 421 में प्रतिवेदित किया , जिसमें याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था, जिसके खिलाफ अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी, उच्च न्यायालय ने सजा को निलंबित करने के बाद अपील के लंबित होने तक जमानत देने के अनुरोध को क्रमिक रूप से खारिज कर दिया। इस प्रकार, यह निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है:

"3. जब किसी दोषी व्यक्ति को सजा की एक निश्चित अवधि की सजा सुनाई जाती है और जब वह किसी वैधानिक अधिकार के तहत अपील दायर करता है, तो अपीलीय अदालत द्वारा सजा के निलंबन पर उदारता से विचार किया जा सकता है जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों। बेशक, अगर सजा के निलंबन के खिलाफ कोई

वैधानिक प्रतिबंध है तो यह एक अलग मामला है। इसी तरह, जब सजा आजीवन कारावास होती है तो सजा के निलंबन के लिए एक अलग दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी कारण से सीमित अवधि की सजा को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे मामलों में अपील की शीघ्र सुनवाई के लिए प्रस्ताव किए जाने पर योग्यता के आधार पर अपील का निपटारा करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। अन्यथा अपील का बहुत मूल्यवान अधिकार समय के प्रवाह की वजह से एक निरर्थक अभ्यास होगा। जब अपीलीय न्यायालय को लगता है कि व्यावहारिक कारणों से ऐसी अपीलों का शीघ्रता से निपटारा नहीं किया जा सकता है, तो अपीलीय न्यायालय को सजा को निलंबित करने के मामले में विशेष चिंता व्यक्त करनी चाहिए ताकि अपील को सही, सार्थक और प्रभावी बनाया जा सके। बेशक, जब जमानत दी जाती है तो अपीलीय अदालतें इसी तरह की शर्तें लगा सकती हैं।

(जोर दिया गया)

28. सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2008) 5 एस. सी. सी. 230 (जेसिका लाल हत्या मामले के रूप में लोकप्रिय) में प्रतिवेदित की गई, इस अदालत को जमानत के लिए प्रार्थना पर दोनों पक्षों द्वारा संदर्भित प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के साथ-साथ विभिन्न न्यायिक घोषणाओं पर विचार करने का अवसर मिला। इस प्रकार, यह निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है:

"19. हम सचेत और सतर्क हैं कि मुख्य मामला (अपील) स्वीकार कर लिया गया है और अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है। योग्यता के आधार पर अवलोकन, एक या दूसरे तरीके से, अपील के लिए एक या दूसरे पक्ष के प्रति पूर्वाग्रहित करने की संभावना है। इसलिए हम अभिलेख पर साक्ष्य की शुद्धता या अन्यथा पर गौर नहीं कर रहे हैं। हालाँकि, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि आज तक, आवेदक को एक सक्षम आपराधिक अदालत द्वारा दोषी पाया गया है और दोषी ठहराया गया है। अतः अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने का प्रारंभिक अनुमान आवेदक के लिए अब उपलब्ध नहीं है।

XXX

XXX

XXX

30. उपरोक्त मामलों में, यह देखा गया है कि एक बार किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद, आम तौर पर, एक अपीलीय अदालत इस आधार पर आगे बढ़ेगी कि ऐसा व्यक्ति दोषी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके बाद भी, कारण दर्ज करके किसी दिए गए मामले में सजा को निलंबित करने के लिए अपीलीय अदालत स्वतंत्र है। लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित है, जैसा कि विजय कुमार [(2002) 9 एससीसी 364 2003 एस. सी. सी. (आ.) 1195:जे. टी. 2002 पू: (1) एस. सी. 60] में देखा गया है कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या जैसे गंभीर अपराध से जुड़े मामले में जमानत के लिए अनुरोध पर विचार करते समय, अदालत को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए जैसे कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप की प्रकृति, जिस तरीके से अपराध करने का आरोप लगाया गया है, अपराध की गंभीरता, हत्या के गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा करने की वांछनीयता आदि। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि ऐसे मामलों में सामान्य प्रथा सजा को निलंबित करना नहीं है और केवल असाधारण मामलों में ही सजा के निलंबन का लाभ दिया जा सकता है।

31. हसमत [(2004) 6 एस. सी. सी. 175:2004 एस. सी. सी. (आ.) 1757:जे. टी. (2004) 6 एस. सी. 6], में इस न्यायालय ने कहा:(एस. सी. सी. पी. 176, पैरा 6)

"6. संहिता की धारा 389 अपील लंबित रहने तक सजा के निष्पादन के निलंबन और आवेदक को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है। जमानत और सजा के निलंबन के बीच अंतर है। धारा 389 के आवश्यक अवयवों में से एक अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा या आदेश के निष्पादन के निलंबन का आदेश देने के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करने की आवश्यकता है। यदि वह कारावास में है, तो उक्त अदालत निर्देश दे सकती है कि उसे जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जाए। लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि प्रासंगिक पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और सजा के निलंबन और जमानत

देने का निर्देश देने वाले आदेश को साधारण रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

32. केवल यह तथ्य कि मुकदमे की अवधि के दौरान, अभियुक्त जमानत पर था और स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था, सजा के निष्पादन के निलंबन और जमानत की मंजूरी की अनुमति नहीं देता है। वास्तव में जो आवश्यक है वह यह विचार करना है कि क्या सजा के निष्पादन को निलंबित करने और जमानत देने के कारण मौजूद हैं।

(जोर दिया गया)

29. अतुल त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, के मामले में, (2014) 9 एस. सी. सी. 177 में प्रतिवेदित किए गए, जिसके तहत -दोषसिद्धि के पूरव के चरण के साथ-साथ दोषसिद्धि के बाद के चरण से संबंधित जमानत देने के लिए प्रार्थना के विचार के अंतर की पहचान करने के अलावा, यह पैरा 14 में निर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है:

"14. याचिकाकर्ता द्वारा अपील की एक प्रति और जमानत के आवेदन की एक प्रति लोक अभियोजक को प्रदान करने से आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 (1) के पहले परंतुक की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा। अपीलीय अदालत लोक अभियोजक को सुने बिना भी जमानत देने से इनकार कर सकती है। हालांकि, यदि अपीलीय अदालत दोषी को जमानत पर रिहा करने पर विचार करने के लिए इच्छुक है, तो लोक अभियोजक को लिखित रूप में कारण दिखाने का अवसर दिया जाएगा कि अपीलार्थी को जमानत पर क्यों नहीं रिहा किया जाए। इस तरह का कड़ा प्रावधान केवल यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है कि अदालत को सभी प्रासंगिक कारकों से अवगत कराया जाए ताकि अदालत इस बात पर विचार कर सके कि क्या यह अपराध करने के तरीके, अपराध की गंभीरता, उम्र, दोषी की आपराधिक पृष्ठभूमि, न्याय-वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास पर प्रभाव आदि को ध्यान में रखते हुए रिहाई के लिए एक उचित मामला है।...."

30. किशोरी लाल बनाम रूपा और अन्य में, (2004) 7 एस. सी. सी. 638 में प्रतिवेदित किया गया इस न्यायालय ने उन कारकों का संकेत दिया है जिन पर हत्या आदि जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत लाभ प्रदान करते समय अदालतों द्वारा विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, इसमें की गई टिप्पणियों को संदर्भित करना उपयोगी है, जो इस प्रकार हैं:

"4. संहिता की धारा 389 अपील लंबित रहने तक सजा के निष्पादन के निलंबन और अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है। जमानत और सजा के निलंबन के बीच अंतर है। धारा 389 के आवश्यक अवयवों में से एक अपीलीय न्यायालय द्वारा या सजा के निष्पादन के निलंबन के आदेश के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करने की आवश्यकता है। यदि वह कारावास में है, तो उक्त अदालत निर्देश दे सकती है कि उसे जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जाए। कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रासंगिक पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और सजा के निलंबन और जमानत देने का निर्देश देने वाले आदेश को साधारण रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए।

5. अपीलीय न्यायालय निष्पक्ष रूप से मामले का आकलन करने और इस निष्कर्ष के लिए कारण दर्ज करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि मामले में सजा के निष्पादन को निलंबित करने और जमानत देने की आवश्यकता है। तत्काल मामले में, सजा के निलंबन और जमानत देने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय के साथ एकमात्र कारक जो प्रतीत होता है, वह है पूर्व अवधि के दौरान स्वतंत्रता के दुरुपयोग के आरोप का अभाव जब अभियुक्त-प्रतिवादी जमानत पर थे।

6. केवल यह तथ्य कि मुकदमे के दौरान उन्हें जमानत दी गई थी और स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं था, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सुनवाई के दौरान दी गई जमानत का प्रभाव महत्व खो देता है जब सुनवाई पूरी होने पर आरोपी व्यक्तियों को दोषी पाया जाता है। केवल यह तथ्य कि उस अवधि के दौरान जब अभियुक्त व्यक्ति मुकदमे के दौरान जमानत पर थे, स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था, सजा के निष्पादन के निलंबन और जमानत देने की अनुमति नहीं देता है। उच्च न्यायालय द्वारा

वास्तव में जिस बात पर विचार किया जाना आवश्यक था, वह यह है कि क्या सजा के निष्पादन को निलंबित करने और उसके बाद जमानत देने के लिए कारण मौजूद थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने सही सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा है।”

31. विजय कुमार बनाम नरेंद्र और अन्य ने (2002) 9 एस. सी. सी. 364 और रामजी प्रसाद बनाम रतन कुमार जायसवाल में और अन्य (2002) 9 एस. सी. सी. 366 में प्रतिवेदित किया, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि से जुड़े मामलों में, यह केवल असाधारण मामलों में है कि सजा के निलंबन का लाभ दिया जा सकता है। विजय कुमार (उपरोक्त) मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या जैसे गंभीर अपराध से जुड़े मामले में जमानत के अनुरोध पर विचार करते समय, अदालत को अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप की प्रकृति, जिस तरीके से अपराध का आरोप लगाया गया है, अपराध की गंभीरता और हत्या के गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की वांछनीयता जैसे प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए।

32. उपरोक्त दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा निम्न में दोहराया गया है वसंत तुकाराम पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 5 एस. सी. सी. 281 में प्रतिवेदित और गोमती बनाम ठाकुरदास और अन्य (2007) 11 एस सी सी 160 में प्रतिवेदित ।

33. अतः, विधि के उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की ओर से यह देखने का प्रयास किया जाना चाहिए कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत और विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए मामले को ऐसा मामला कहा जा सकता है जिसमें अंततः दोषी को बरी किए जाने की उचित संभावना हो। यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होना है, तो एक आवश्यक परिणाम के रूप में, हमें यह कहना होगा कि यदि अंततः दोषी इस न्यायालय के हाथों बरी होने का हकदार प्रतीत होता है, तो उसे अपील के समापन तक बहुत लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जाना चाहिए, जिसमें आमतौर पर निर्णय और निपटान में बहुत लंबा समय लगता है। हालांकि, यह पता लगाने के लिए अभ्यास करते समय कि क्या दोषी के बरी होने की उचित संभावना है, जिस पर गौर किया जाना चाहिए वह स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ ऐसा जो अभिलेख में बहुत स्पष्ट या स्थूल है,

जिसके आधार पर न्यायालय प्रथम दृष्टया इस संतोष पर पहुंच सकता है कि दोषसिद्धि धारणीय नहीं हो सकती है। अपीलीय न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के स्तर पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए और अभियोजन के मामले में यहां या वहां कुछ खामियों या खामियों को उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस तरह का तरीका सही नहीं होगा।

34. प्रस्तुत मामले में, उच्च न्यायालय ने जो किया है वह अस्वीकार्य है। उच्च न्यायालय ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, प्रथम सूचना प्रतिवेदन में कुछ ओवर-राइटिंग आदि जैसे मुद्दों पर गौर किया है। दोषियों द्वारा दायर अपीलों की अंतिम सुनवाई के समय इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। अभिलेख पर साक्ष्य की साधारण जाँच करने पर, हम दोषियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील से आने वाली दलीलों से सहमत होने में असमर्थ हैं कि या तो दोषियों के खिलाफ कोई मामला नहीं है या उनके खिलाफ सबूत इतने कमजोर और कमजोर प्रकृति के हैं कि अंततः सभी संभावनाओं में कार्यवाही उनके पक्ष में समाप्त हो जाएगी। इसी कारण से हम दोषियों से उनके विद्वान वरिष्ठ वकील के माध्यम से आ रही इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि जब तक वे आरोपों से दोषमुक्त नहीं पाए जाते, तब तक उन्हें काफी लंबे समय तक सलाखों के पीछे रखना अर्थहीन, अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा।

35. मामले के समग्र दृष्टिकोण से, हम आश्चर्य हैं कि उच्च न्यायालय ने दोषियों की सजा के मूल आदेश को निलंबित करने और उनकी आपराधिक अपीलों के अंतिम निपटारे तक जमानत पर उनकी रिहाई में एक गंभीर त्रुटियों की है।

36. वास्तव में, अभियोजन अभिकरण के रूप में राज्य से उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने की उम्मीद की गई थी, लेकिन किसी न किसी कारण से, राज्य ने आगे कुछ नहीं करना उचित समझा। अंततः, यह मूल प्रथम सूचक (मृतक का भाई) है जिसे इस न्यायालय के समक्ष आना पड़ा।

37. हम यह स्पष्ट करते हैं और यह बिना कहे ज्ञात है कि मामले के योग्यता को छूने वाली कोई भी टिप्पणी विशुद्ध रूप से वर्तमान अपीलों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से है और इसे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित आपराधिक अपीलों में अंतिम राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाए।

38. परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें सफल होती हैं और एतद्द्वारा अनुमति दी जाती है।

39. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है

40. दोषियों को आज से तीन दिन की अवधि के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायक: आर्ष चौधरी, एलसीआरए)